मोदी जी तो महान कलाकार हैं, वे गलत नहीं हो सकते

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सदी के महानतम कलाकार हैं। इसके बावजूद आज भारत के लोग उन्हें जी भर कर कोस रहे हैं। उन्हें अनपढ़, झूठा पाखंडी बता कर उन पर दुनिया भर के आरोप लगाये जा रहे हैं। उन पर देश की संपत्तियां बेचने, बैंकों का सारा धन अपने मित्रों को बांट देने का आरोप है। जब बांटने के लिये धन कम पड़ता है तो मोदीजी टैक्स पर टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ाने से गुरेज नहीं करते।

अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। एक मदारी जिसने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होती और अपने हुनर एवं कलाकारी के बल पर जहां चाहे बीच सड़क पर सैंकड़ों लोगों का मजमा लगा कर अपना तमाशा दिखाने के लिये बांधे रहता है। कभी अपने झोले से अंडा निकाल कर उसका कबूतर बना देता है और कबूतर का मुर्गा बना देता है तो कभी ताश के पत्तों को रुपये बना देता है। जब वह बोलता है कि बच्चा बजाओ ताली तो सभी लोग ताली बजाते हैं और चलते वक्त अपनी-अपनी जेब से कुछ न कुछ देकर जाते हैं। जिस तरह से अनपढ़ मदारी ने लोगों को बांध कर रखने का गुण होता है उसी तरह का हुनर मोदी जी को भगवान की ओर से दिया गया अनमोल तोहफ़ा है।

वर्ष 2012-13 के दौरान तत्कालीन शासन से त्रस्त जनता को मोदी ने अपनी कला के जाल में फंसाया। उन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने, प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने जैसे लुभावने नारों के साथ-साथ 15-15 लाख रुपये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने का जुमला उड़ाया। इस तरह के जुमला छोड़ने में मोदी की क्या गलती है? गलती तो इन मूर्ख लोगों की है जिन्होंने मदारी के इस खेल को समझने का कोई प्रयास ही नहीं किया। 'अबकी बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे' जैसे लुभावने नारों में फंसकर जनता ने मोदी को परमेश्वर द्वारा भेजे गये फरिश्ते का दर्जा दे डाला।

जनता ने इस शख्स का इतिहास एवं कार्यशैली जानने व समझने का रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि वे जिस आरएसएस से आते हैं उसका काला इतिहास क्या है? जब देश वासी स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे तो आरएसएस अंग्रेजी हुकूमत कि न केवल चापलूसी कर रहा था बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ़ सरकार के मुखबिर बने हुए थे। आज जिस तिरंगा यात्रा की बातें बढ़-चढ़ कर करते हैं उसे तो ये लोग अपशकुन बताते थे, वर्ष 2002 तक तो इन्होंने अपने नागपुर स्थित मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगने दिया था। जब कुछ लोगों ने जबरदस्ती लगा दिया तो उन पर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। इनका एक मात्र एजेंडा मुस्लिम व ईसाइयों के विरुद्ध हिन्दुओं की भावनाएं भड़का कर सत्ता हासिल करना रहा है।

सन् 2002 के गुजरात में जब भाजपा के जीतने के कोई आसार नहीं थे तो मोदी जी ने भयंकर मुस्लिम नरसंहार करवा कर न केवल गुजरात जीत लिया बल्कि दिल्ली की गद्दी हथियाने का रास्ता भी खोज निकाला। इसी रास्ते पर चलते हुए एक के बाद एक सफलता की सीढियां चढ़ते गए। इस हकीकत को जब जनता न समझे और मोदी-मोदी ही चिल्लाये तो फिर इसमें मोदी जी का क्या दोष है? सन् 2013-14 में वे अडाणी के जहाज में उड़ कर घातक चुनावी प्रचार कर रहे थे और पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था तो जनता को वह सब नज़र क्यों नहीं आया? जिन पूंजीपतियों के धन-बल से मोदी ने सत्ता हथियाई हो तो देश की संपत्ति उनके नाम क्यों नहीं कर देंगे। यही सब तो मोदी जी कर रहे हैं। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि मोदी जी पूरी ईमानदारी, निष्ठा व मेहनत के साथ बीना कोई छुट्टी लिये बीसियों घंटे प्रति दिन काम करके अपने फर्ज को पूरा करने में जुटे हैं जिसके लिये वे इस पद पर विराजमान हुए। बाकी जो कसर अभी तक बची है उसे वे अगर जनता ने मौका दिया तो अगली टर्म में पूरा कर देंगे। तब न कोई संविधान होगा, न तिरंगा बचेगा और न ही कोई उन पर सवाल उठाने वाला रहेगा।

हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभिनव भारत संगठन...

पेज पांच का शेष

पढ़ते हुए तिरंगे की जगह राष्ट्रीय ध्वज का भी जिक्र किया कि वह कैसा होगा, उसकी लंबाई-चौड़ाई कितनी होगी, किस रंग का होगा उस पर क्या-क्या छपा होगा। कैसे उसकी चार मिसालें चार वेदों को प्रतिबिंबित करेंगी। सोचिए देश की आर्मी का इतना बड़ा अफसर होते हुए भी कर्नल पुरोहित और उसके साथी देश के तिरंगे को हटा कर अपनी विचारधारा का झंडा लागू करना चाहते थे।

एक ऐसी सनक थी, अब आप कह सकते हैं कि ऐसी सीक्रेट मीटिंगें तो होती रहती हैं, ऐसी बात तो लोग करते ही रहते हैं धरातल पर कुछ नहीं होता, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। अभिनव भारत के कार्यकर्ताओं का तीन बम ब्लास्ट में भी हाथ था, मालेगांव ब्लास्ट में तो था ही जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई। दो अन्य की बात कर्नल पुरोहित और मेजर उपाध्याय बताते हैं फरीदाबाद मीटिंग मालेगांव ब्लास्ट से पहले की थी। उस मीटिंग में कर्नल पुरोहित कहता है कि आज मैं आपको ऐसा रहस्य बताऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं बताया, हमने इससे पहले दो सफल विस्फोट किए हैं। फरीदाबाद मीटिंग से एक दिन पहले रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने इन दो ऑपरेशंस में से एक बारे में स्वामी अमृतानंद को अपनी एक निजी बातचीत में बताया था। मेजर रमेश उपाध्याय ने स्वामी अमृतानंद को बताया कि अभिनव भारत के कुछ कार्यकर्ताओं का मुस्लिमों और ईसाइयों में डर फैलाने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। इन कार्रवाइयों को जीवित रखना चाहिए जैसे हैदराबाद मस्जिद में हुआ ब्लास्ट, इसमें कोई आईएसआई इन्वॉल्व नहीं थी बल्कि हमारे ही लोग थे। इसके अलावा अन्य विस्फोट के बारे में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली बताती है कि ये हमले शायद नांदेड़ ब्लास्ट, या परवड़ी या जालना ब्लास्ट हो सकते हैं क्योंकि इन धमाकों में भी अभिनव भारत का कार्यकर्ता राकेश धावड़े शामिल पाया गया था। राकेश धावड़े मालेगांव ब्लास्ट के लिए हुई सीक्रेट मीटिंग्स में भी शामिल होता था।

सवाल यह है कि क्या अभिनव भारत संगठन और उसके कार्यकर्ता एक अलग थलग ग्रुप की तरह पड़े हुए थे जो एक अन रियलिस्टक प्लान लेकर चल रहे थे? भला

मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दयानन्द पाण्डे

ये कुछ लोग इतनी बड़ी सरकार को उखाड़ फेकने और तख्ता पलट करने का हास्यास्पद प्लान सोच भी कैसे रहे थे। लेकिन ये सच नहीं है ये कोई अलग थलग पड़े हुए ग्रुप नहीं थे, या कुछ कम लोग नहीं थे, अभिनव भारत के कार्यकर्ता भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंगदल जैसे हिंदूवादी मुख्यधारा के संगठनों से ही आए थे।

दूसरी बात समय समय पर आरएसएस और भाजपा जैसे संगठनों ने अभिनव भारत और उसके पदाधिकारियों का बचाव किया। जब ये सभी आरोपी जमानत पर बाहर आते हैं तो इनके जेलों से बाहर आने पर आरएसएस व भाजपा समर्थक मीडिया ने भी इनको एक हीरो की तरह पेश किया अपराधियों की तरह पेश नहीं किया।

अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि जमानत पर बाहर आने के बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ? क्या ये जेल गए, क्या इनको सजा मिली? इस सवाल के जवाब की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प और रोचक है। साल 2008 के अंत में मालेगांव ब्लास्ट की साजिश रचने के आरोप में ये सारे आरोपी जेल भेज दिए जाते हैं और इन्हें जेल भेजने वाले अधिकारी का नाम था हेमंत करकरे। ये सारे आरोपी 2014 तक जेल में रहते हैं इस बीच 26/11मुंबई अटैक के बाद सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए एनआईए का गठन किया। एनआईए के गठन के बाद साल 2011 में मालेगांव ब्लास्ट की जांच महाराष्ट्र एटीएस से लेकर एनआईए को दे दी जाती है।

साल 2014 में सरकार बदल जाने के बाद मामला बदल जाता है, धीरे-धीरे इन आरोपियों के खिलाफ केस कमजोर कर दिया जाता है। गवाह पलट जाते हैं सबूत मिटा दिए जाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की ओर से कोर्ट में पेश होने वाली सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में बयान दिया कि सरकार बदलने के बाद एनआईए के एक अधिकारी ने मुझे आकर कहा कि आपके लिए एक मैसेज है कि इस केस में अब सॉफ्ट चलना है। रोहिणी सालियान ने बताया कि सुनवाई से एक दिन पहले एनआईए का वह अधिकारी दोबारा मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि ऊपर से निर्देश हैं कि इस बार कोर्ट में आपकी जगह कोई और अपीयर होगा। इस तरह अंततः रोहिणी सालियान को इस केस से एनआईए की ओर से सरकारी वकील की जिम्मेदारी से हटा दिया जाता है।

यह लगभग स्पष्ट संदेश था कि नई सरकार इस केस में एनआईए और सरकारी वकीलों से क्या चाहती है। धीरे धीरे गवाह पलटते चले जाते हैं, केस कमजोर होता चला जाता है। कोर्ट उन्ही सबूतों के आधार पर फैसला देती है जो जांच एजेंसी उसके सामने सबूत के रूप में पेश करती है। अगर जांच एजेंसी सबूतों के साथ खेल करे तो कोर्ट क्या कर सकती है, जैसे सबूत कोर्ट को दिखाए जाएंगे कोर्ट लगभग वैसा ही निर्णय देगा। यही हुआ, साल 2017 के अप्रैल महीने में गवाहों के बयान बदलने के कारण बांबे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार कोर्ट ने जमानत देने का आधार ये माना कि जिन दो गवाहों स्वामी अमृतानंद देव और राकेश धावड़े की गवाही के आधार पर साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया था उन दोनों ने ही अपने बयान वापस ले लिए हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा एक महिला है और जेल में आठ साल हो चुके हैं और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं बिना सबूत के उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता।

इस तरह साध्वी प्रज्ञा जमानत पर जेल से बाहर आई। साध्वी प्रज्ञा की जमानत के तीन महीने के बाद कर्नल पुरोहित को अगस्त में जमानत मिल जाती है। कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में दावा किया कि वह तो सेना में खुफिया एजेंसी में था और अभिनव भारत की कार्रवाइयों पर नजर रखने के लिए अभिनव भारत की सीक्रेट मीटिंग्स अटेंड करता था ताकि वहां से खुफिया रिपोर्ट निकाल सके और सेना में दे सके, हालांकि कोर्ट ने कर्नल पुरोहित के इस तर्क को सही नहीं माना। कर्नल पुरोहित ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि वह नौ साल जेल में रह चुका है अगर बम सप्लाई करने के आरोप में वह दोषी पाया भी जाता तो उसे अधिकतम सात साल की ही सजा हो सकती थी, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। अंततः कर्नल पुरोहित को अगस्त 2017 में जमानत पर रिहाई मिल जाती है। कर्नल पुरोहित के बाद बाकी आरोपियों को भी इस आधार पर जमानत मिल जाती है कि मुख्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है।

भारतीय संविधान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और तिरंगा जैसे राष्ट्रीय ध्वज को बदलने की साजिश रचने वाले, मालेगांव ब्लास्ट को अंजाम देने वाले, आज जमानत पर बाहर हैं, उनमें से एक वर्तमान सरकार वाली पार्टी से सांसद हैं यानी वो जनता की जन प्रतिनिधि हैं लेकिन एक बात सीखने के लिए है कि किस तरह बम ब्लास्ट का माहौल बना कर और हिंदू- मुस्लिम को लड़ा कर कुछ लोग इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, कमोबेश आज भी यही स्थिति है आज भी हिंदू -मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है लेकिन अपने पड़ोसी मुस्लिम या हिंदू से नफरत करने के बजाय एक बार यह जरूर सोचना चाहिए कि हमें आपस में लड़ा कौन रहा है? कौन आपको भड़का कर अपने पक्ष में करना चाहता है। दोनों ही पक्ष के लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए।

श्याम मीरा सिंह यू-टयूब पत्रकार है। इन्होंने एटीएस के दस्तावेजों के आधार पर ये खबर तैयार की है।

संसदीय इतिहास के झरोखे से /मोदी और पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा विपक्ष से संवाद करने की परंपरा

डॉ. जुगल किशोर

भारत के संसदीय इतिहास के सर्वे से उजागर होता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू एक कुशल राजनीतिक नेता व राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने प्रजातांत्रिक संवैधानिक मूल्यों की स्थापना कर देश के प्रजातंत्र, संसदीय शासन प्रणाली व देश के संविधान की स्थापना की।

नेहरू जी विपक्ष का समुचित आदर करते थे और उन्होंने विपक्ष को उचित स्थान दिया था। यहां तक कि उन्होंने अपने मंत्रीमंडल में विरोधी विचाराधारा वाले व्यक्ति भी शामिल किए थे। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल कर उद्योग व आपूर्ति मंत्री बनाया था। नेहरू जी का मानना था कि मजबूत विपक्ष का न होने का अर्थ है कि व्यवस्था में अहम खामियां हैं।

नेहरू जी सदन की कार्यवाही में पूरी रुचि रखते थे और सदन में उपस्थित रहकर सांसदों विशेषकर विपक्षी नेताओं के आलोचनात्मक भाषणों को ध्यान से सुनते थे। उन्होंने विपक्ष की आवाज का कभी मजाक नहीं उड़ाया व उन पर कभी तंज नहीं कसा। विपक्षी सांसद अटल बिहारी वाजयेपी के भाषण में नेहरू जी की तीखी आलोचना पर क्रोधित होने की अपेक्षा नेहरू जी ने वाजपेयी जी को प्रोत्साहित किया।

इस प्रकार नेहरू जी ने स्वस्थ संसदीय व लोकतांत्रिक परम्पराओं को स्थापित कर मजबूत प्रजातंत्र की नींव रखी जिसका अनुकरण आने वाले लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने किया और विपक्ष के साथ संवाद बनाए रखा। कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासन काल की एक घटना उल्लेखनीय है। 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी का एक घुटना खराब हो चुका था और दूसरा खराब होने के कगार पर था, जिसका इलाज अमेरिका में हो सकता था। इस बात का पता लगने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने वाले आधिकारिक शिष्टमंडल का सदस्य बनाते हुए कहा कि वे न्यूयार्क (अमेरिका) से अपना पूरा इलाज करवाकर आएं। इसके अतिरिक्त राजीव जी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि वाजपेयी जी अपना इलाज कराकर ही वापस आएं। गौरतलब है कि इस घटना के बारे में राजीव जी ने कभी चर्चा नहीं की। राजीव गांधी की हत्या के बाद वाजपेयी जी ने अपने शोक संदेश में इस रहस्य को उजागर करते हुए कहा कि वे राजीव गांधी के कारण जिंदा हैं।

लेकिन 2014 में भाजपा के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्हें विपक्ष की मौजूदगी सहन नहीं है। उन्होंने अपनी हर सभा में कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। वे विपक्ष का मजाक बनाने और अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सरकारी समारोहों में भी विपक्ष पर व्यंग्य कसते रहते हैं। विपक्ष को बदनाम करने व कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई व आयकर विभाग का दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हैं। सरकार की नीतियों व मोदी जी के आलोचकों पर देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी व विदेशी षणयंत्र का हिस्सा होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मोदी जी संसद की कार्यवाही में कोई रुचि नहीं रखते, वे कभी कभार संसद आते हैं और जब आते हैं तो उसे इवेंट बनाकर चले जाते हैं।

वे जनता विशेषकर विपक्ष के साथ संवाद स्थापित करने की अपेक्षा मोनोलॉग करने के पक्षधर हैं। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली, प्रजातांत्रिक व संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर तानाशाही व व्यक्तिगत शासन व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास के आरोप मोदी जी पर लग रहे हैं।